भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1455
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्णतः लागू करने वाले राज्य

1455. **श्री अशोक कुमार रावतः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कितने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से लागू किया है;
(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन में राज्यों को किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार इस कारण से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। एनईपी 2020 में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न समय-सीमाओं के साथ-साथ, नियम और कार्यप्रणाली की व्यवस्था है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से उत्तरदायी हैं। एनईपी इस नीति के निष्पादन के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा सावधानीपूर्वक योजना, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन का भी प्रावधान करती है। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के विनियामक और कार्यान्वयन निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल की है।

एनईपी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करने और नवीन विचारों पर चर्चा करने के लिए, समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रो, शैक्षणिक संस्थानों, अन्य हितधारकों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। जून 2022 में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन; जून 2022 में आयोजित मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन; अगस्त 2022 में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की

7वीं बैठक; अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022, 2023 और 2024, 27 जुलाई 2024 को आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। एनईपी 2020 को लागू करने हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों और पद्धतियों का प्रसार करने के लिए 12 और 13 नवंबर 2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के साथ उच्चतर और तकनीकी शिक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। दिनांक 10 और 11 जुलाई 2025 को गुजरात के केवडिया में एक केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें शैक्षिक परिवर्तन के संचालकों के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका और वर्ष 2047 के विकसित भारत में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया; एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की दिशा तय की गई; एनईपी 2020 के प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के तहत बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 30 अप्रैल से 01 मई, 2025 तक आयोजित की गई, जिसमें एनईपी कार्यान्वयन के लिए यूजीसी विनियम, बहु-विषयक शिक्षा के लिए क्लस्टरिंग और सहयोग, कौशल और उद्योग संपर्क के एकीकरण के माध्यम से समग्र शिक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में कुलपतियों, प्रख्यात शिक्षाविदों और राज्य के अधिकारियों ने भाग लिया।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन समकक्षता और अधिगम के परिणामों में सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 02.07.2025 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 250 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य आकर्षणों में परख प्रसार पोर्टल का शुभारंभ, राज्य-स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुतियां, बोर्ड समकक्षता के लिए रूपरेखा पर विचार-विमर्श और एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप अधिगम के परिणामों को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां शामिल थीं।

एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के बारे में लोगों तक पहुँच और जागरूकता फैलाने के लिए 84 केंद्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएफआई) और 404 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए एक कायाक्रम शुरू किया गया है जिसमें प्रत्येक सीएफआई को नजदीक के भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित 5-7 राज्य विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी 2020 के साथ अनुकूलित किया गया है। जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, वर्ष 2021-22 से 2025 26 तक का बजट आवंटन निम्नलिखित है: -

वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
बजट आवंटन (रु. करोड़ में)	93,224.31	1,04,277.72	1,12,899.47	1,21,117.77	1,28,650.05

शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनईपी 2020 के अनुरूप संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में 1,39,289.48 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

*****